भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3114

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

असम में नदी तट अपरदन जोखिम प्रबंधन

3114. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में, विशेषकर ग्वालपाड़ा और धुबरी के लिए जलवायु अनुकूल ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट अपरदन जोखिम प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास धुबरी जिले में 22027.63 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत वाली उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की कोई अनुमानित समय-सीमा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता भी प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्तपोषित, 542.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली असम-ग्वालपाड़ा धुबरी उप परियोजना (जोन-डी) में "जलवायु अनुकूल ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना (सीआरबीआईएफआरईआरएमपी)" नामक योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा मूल्यांकन किया गया और दिसंबर 2023 में आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति की 154वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

असम सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने असम में विशेष रूप से ग्वालपाड़ा और धुबरी जिले के लिए सीआरबीआईएफआरईआरएमपी (जोन-डी) का कार्य निष्पादन शुरू कर दिया है और राज्य द्वारा वर्ष 2024 में सीआरबीआईएफआरईआरएमपी (जोन-डी) के चरण-I के ऋण पर हस्ताक्षर करने के बाद, ग्वालपाड़ा जिले सहित सभी उप परियोजना क्षेत्रों में 168.61 करोड़ रुपये की राशि का कार्य शुरू हो गया है।

*****